मद्रास राज्य

बनाम

वी.जी. रॉ

भारत और राज्य संघ का ट्रॉवेंकर-कोचीन।

(हस्तक्षेप करने वाले)

[पतंजलि शास्त्री सी.जे., मेहर चंद महाजन,

मुखर्जी, दास और चंद्रसेखर अय्यर, जेजे.)

भारतीय आपराधिक कानून संशोधन (मद्रास) अधिनियम, 1950 द्वारा संशोधित भारतीय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (1908 का XIV)। 15 (2) (ख), 16-अधिसूचना द्वारा संघों को अवैध घोषित करने के लिए राज्य को सशक्त बनाने वाला कानून-न्यायिक जांच या अधिसूचना की सेवा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। संघ या पदाधिकारी पर प्रतिबंध-कानून की वैधता-संघ बनाने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध-भारत का संविधान, अनुच्छेद 19 (1) (ग), (4)।

भारतीय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908 की धारा 15 (2) (बी) को भारतीय आपराधिक कानून संशोधन (मद्रास) अधिनियम, 1950 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसे "गैरकानूनी संघ" की परिभाषा के भीतर शामिल किया गया है-एक संघ जिसे राज्य द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आधार पर गैरकानूनी घोषित किया गया है (अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाना है) कि ऐसा संघ (i) सार्वजनिक शांति के लिए खतरा है, या (ii) सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करता है या अपने उद्देश्य के लिए ऐसा हस्तक्षेप करता है, या (iii) कानून के प्रशासन में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करता है, या अपने उद्देश्य के लिए

ऐसा हस्तक्षेप करता है। अधिनियम की धारा 16 में जैसा कि संशोधन किया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि धारा 15 (2) (बी) के तहत एक अधिसूचना (i) उस आधार को निर्दिष्ट करेगी जिस पर इसे जारी किया गया है और ऐसे अन्य विवरण, यदि कोई हैं, जो 2-7 एस. सी. भारत/71 की आवश्यकता पर असर डाल सकते हैं और (ii) किसी भी पद के लिए एक उचित अवधि निर्धारित करें। अधिसूचना जारी करने के संबंध में राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व करने के लिए संघ के वाहक या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति। धारा 16ए के तहत सरकार को अधिसूचना में निर्धारित समय की समाप्ति के बाद एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष मामले को रखने के लिए प्रतिनिधित्व करने और अधिसूचना को रद्द करने की आवश्यकता थी यदि बोर्ड को लगता है कि ऐसी अधिसूचना जारी करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। हालाँकि, संघ और उसके सदस्यों या पदाधिकारियों को अधिसूचना के पर्याप्त संचार के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यह स्वीकार किया गया कि धारा 15 (2) (बी) के तहत परीक्षण, जैसा कि संशोधित किया गया था, एक व्यक्तिपरक था और आधारों का तथ्यात्मक अस्तित्व या अन्यथा न्यायसंगत मुद्दा नहीं था और सवाल यह था कि क्या धारा 15 (2) (बी) असंवैधानिक और शून्य थी|

अभिनिर्धारित, (नीचे बताए गए कारणों के लिए) कि धारा 15 (2) (बी) ने अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत संघ बनाने के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए। 19 (I) (c), जो अनुच्छेद के अर्थ के भीतर उचित नहीं थे। 19 (4) और इसलिए असंवैधानिक और अमान्य था। अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत संघ या संघ बनाने का मौलिक अधिकार। (ग) संविधान के प्रयोग के लिए इतनी व्यापक और विविध गुंजाइश है, और इसकी कटौती धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में ऐसी संभावित प्रतिक्रियाओं से भरी हुई है, कि इस तरह के अधिरोपण के आधारों को न्यायिक जांच में उनके तथ्यात्मक और कानूनी दोनों पहलुओं में विधिवत परीक्षण की अनुमति दिए बिना, ऐसे अधिकार पर

प्रतिबंध लगाने का अधिकार कार्यकारी सरकार को सौंपना एक मजबूत तत्व है, जिसे अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का न्याय करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए। 19 (एल) (सी)। एस के तहत सरकार की अधिसूचना के पर्याप्त संचार के लिए एक प्रावधान का अभाव। 15 (2) (बी) व्यक्तिगत सेवा या सेवा द्वारा संघ और उसके सदस्यों और पदाधिकारियों को संलग्न करना भी एक गंभीर दोष था।

सरकार या उसके अधिकारियों की उन सामग्रियों की समीक्षा करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड के साथ व्यक्तिपरक संतुष्टि के सूत्र को, जिन पर सरकार नागरिक को गारंटी दी गई बुनियादी स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है, केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में और संकीर्ण सीमाओं के भीतर ही उचित माना जा सकता है।

मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों की तर्कसंगतता पर विचार करते हुए, विवादित कानून के मूल और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं की तर्कसंगतता के दृष्टिकोण से जांच की जानी चाहिए और जहां भी निर्धारित किया गया हो, प्रत्येक व्यक्तिगत क़ानून पर तर्कसंगतता का परीक्षण लागू किया जाना चाहिए और सभी मामलों में लागू होने के रूप में तर्कसंगतता का कोई अमूर्त मानक या सामान्य पैटर्न निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति, लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, इस तरह से बुराई की सीमा और तात्कालिकता को दूर करने की मांग, अधिरोपण का अनुपात, उस समय की प्रचलित स्थितियों को न्यायिक फैसले में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे मायावी कारकों का मूल्यांकन करने और किसी भी मामले की सभी परिस्थितियों में जो उचित है, उसके बारे में अपनी अवधारणा बनाने में, यह अपरिहार्य है कि मद्रास के सामाजिक दर्शन और निर्णय में भाग लेने वाले न्यायाधीशों के मूल्यों का पैमाना एक महत्वपूर्ण भूमिका

निभाए, और ऐसे मामलों में विधायी निर्णय में उनके हस्तक्षेप की सीमा केवल उनकी जिम्मेदारी और आत्मसंयम की भावना और इस गंभीर प्रतिबिंब से निर्धारित की जा सकती है कि संविधान न केवल लोगों के सोचने के तरीके के लिए है, बल्कि सभी के लिए है, और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत ने प्रतिबंधों को लागू करने को अधिकृत करने में उन्हें उचित माना है।

ए.के. गोपालन बनाम राज्य ([1950] एस.सी.आर. 88) और डॉ. खरे बनाम पंजाब राज्य ([1950] एस.सी.आर. 519)।

अपीलार्थी (मद्रास राज्य) की ओर से भारत के महान्यायवादी एम. सी. सीतलवाड़ (एस. गोविंद स्वामीनाथन और आर. गणपति अय्यर) उनके साथ।

प्रत्यर्थी के लिए सी.आर. पट्टाभि रमन।

भारत संघ के लिए एम.सी. सीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी (जी.एन. जोशी, उनके साथ)।

टी. एन. सुब्रमण्य अय्यर, त्रावणकोर-कोचीन के महाधिवक्ता, (उनके साथ एम.आर. कृष्ण पिल्लई) त्रावणकोर-कोचीन राज्य के लिए।

31 मार्च, 1952 को न्यायालय का निर्णय पतंजलि शास्त्री सी.जे. द्वारा दिया गया था।

यह भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1908 (अधिनियम सं. 1908) की धारा 15 (2) (बी) का न्यायनिर्णयन करते हुए मद्रास में उच्च न्यायालय के एक आदेश की अपील है। भारतीय दंड विधि संशोधन (मद्रास) अधिनियम, 1950 (जिसे इसके बाद विवादित अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा संशोधित 1908 का XIV) को असंवैधानिक और अमान्य बताते हुए और सरकारी आदेश संख्या 1517, सार्वजनिक (सामान्य) विभाग, दिनांक 10 मार्च, 1950 को रद्द करते हुए, जिसके तहत राज्य

सरकार ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी नामक एक संस्था को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था।

प्रत्यर्थी, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी का महासचिव था, ने 10 अप्रैल, 1950 को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन किया और शिकायत की कि विवादित अधिनियम और 10 मार्च, 1950 का आदेश, जिसके तहत उसे जारी किया जाना था, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) द्वारा उसे संघ या संघ बनाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और उचित राहत की मांग करता है। उच्च न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों (राजमन्नार सी.जे., सत्यनारायण राव और विश्वनाथ शास्त्री जे.) की एक पूर्ण पीठ द्वारा 14 सितंबर, 1950 को आवेदन को मंजूरी दी और अनुच्छेद 132 के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान किया। मद्रास राज्य ने यह अपील की है।

ऊपर उल्लिखित सरकारी आदेश इस प्रकार हैः-

> "क्योंकि राज्य सरकार की राय में, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, मद्रास के रूप में जानी जाने वाली एसोसिएशन, कानून के प्रशासन और कानून और व्यवस्था के रखरखाव में अपने उद्देश्य के लिए हस्तक्षेप करती है, और सार्वजनिक शांति के लिए खतरा है;
>
> इसलिए, अब, मद्रास के महामहिम राज्यपाल, भारतीय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम XIV) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त संगठन को उक्त अधिनियम के अर्थ के भीतर एक गैरकानूनी संगठन घोषित करते हैं।"

यह आदेश की कोई प्रति प्रत्यर्थी या सोसायटी के किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं दी गयी थी, लेकिन इसे विवादित अधिनियम द्वारा आवश्यक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

प्रत्यर्थी के शपथ पत्र में समाज के घोषित उद्देश्य हैं:

(ए) सभी विज्ञानों और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान में उपयोगी ज्ञान को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, प्रसार करना और लोकप्रिय बनाना;

(बी) लोगों के बीच राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, प्रसार करना और लोकप्रिय बनाना;

(सी) सभी सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन और समझ को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना और सामाजिक और राजनीतिक सुधार लाना; और

(डी) कला, साहित्य और नाटक को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और लोकप्रिय बनाना।

हालाँकि, सरकार के उप सचिव, सार्वजनिक विभाग द्वारा अपीलकर्ता की ओर से एक जवाबी-हलफनामे में कहा गया था कि, सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोसायटी मद्रास में कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय रूप से मदद कर रही थी, जिसे अगस्त 1949 में पार्टी की ओर से प्रचार करने के लिए अपने सचिव के माध्यम से अपने धन का उपयोग करके गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था, और यह कि सोसाइटी के घोषित उद्देश्यों का उद्देश्य अपनी वास्तविक गतिविधियों को छिपाना था।

जैसा कि मद्रास संशोधन अधिनियम (सं। 1950 का 11) 12 अगस्त, 1950 को पारित किया गया था, याचिका के लंबित होने के दौरान, जिसे 21 अगस्त, 1950 को सुनवाई के लिए लिया गया था, इसमें शामिल मुद्दों को संशोधित मूल अधिनियम के

आलोक में निर्धारित किया जाना था। मुद्दों को समझने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करना आवश्यक है। मद्रास अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले भौतिक प्रावधान इस प्रकार थेः -

"15. इस भाग में-

(1) "संघ" का अर्थ है व्यक्तियों का कोई संयोजन या निकाय, चाहे वह किसी विशिष्ट नाम से जाना जाए या न जाना जाए; और

(2) "गैरकानूनी संघ" का अर्थ है एक ऐसा संघ-

(ए) जो व्यक्तियों को हिंसा या धमकी के कृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है या सहायता करता है या जिसके सदस्य आदतन ऐसे कार्य करते हैं, या

(बी) जिसे प्रांतीय सरकार द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है।

16. यदि प्रांतीय सरकार की राय है कि कोई संघ कानून के प्रशासन या कानून और व्यवस्था के रखरखाव में हस्तक्षेप करता है या अपने उद्देश्य के लिए हस्तक्षेप करता है, या यह कि यह सार्वजनिक शांति के लिए खतरा है, तो प्रांतीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकती है।"

संशोधनकारी अधिनियम ने धारा 15 (2) में खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखाः-

"(बी) जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आधार पर गैरकानूनी घोषित किया गया है (अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाना है) कि ऐसा संगठन-

(i) सार्वजनिक शांति के लिए खतरा है, या

(ii) सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करता है या इसके उद्देश्य के लिए ऐसा हस्तक्षेप करता है, या

(iii) कानून के प्रशासन में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करता है, या इसके उद्देश्य के लिए ऐसा हस्तक्षेप करता है।"

पुरानी धारा 16 के लिए, धारा 16 और 16ए को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया थाः

"(1) किसी भी संघ के संबंध में धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत जारी की गई अधिसूचना-

(ए) उस आधार को निर्दिष्ट करेगी जिस पर इसे जारी किया गया है, इसके जारी होने के कारण और ऐसे अन्य विवरण, यदि कोई हों, जो इसकी आवश्यकता पर असर डाल सकते हैं; और

(बी) किसी भी पदाधिकारी या संघ के सदस्य या अधिसूचना जारी करने के संबंध में राज्य सरकार को अभ्यावेदन करने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक उचित अवधि निर्धारित करें।

(2) उप-धारा (1) की किसी भी बात में राज्य सरकार से ऐसे किसी भी तथ्य का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसे वह सार्वजनिक हित के खिलाफ मानता है।"

धारा 16ए के तहत सरकार से अभ्यावेदन करने के लिए अधिसूचना में निर्धारित समय की समाप्ति के बाद, उसके द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष अधिसूचना और अभ्यावेदन की एक प्रति, यदि कोई हो, ऐसी समाप्ति से पहले रखने की आवश्यकता होती है, और बोर्ड को राज्य सरकार या संबंधित संघ के किसी पदाधिकारी या सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी अधिक जानकारी मांगने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करना चाहिए और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि बोर्ड द्वारा यह पाया जाता है कि संबंधित संघ के संबंध में अधिसूचना जारी करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो सरकार को अधिसूचना को रद्द करने की आवश्यकता है।

धारा 17 का कोई संशोधन नहीं है जो किसी गैरकानूनी संघ की सदस्यता या प्रबंधन के लिए और ऐसे संघ की बैठकों में भाग लेने या उसके उद्देश्यों के लिए योगदान करने, प्राप्त करने या अनुरोध करने के लिए कारावास या जुर्माने या दोनों के रूप में दंड निर्धारित करता है। धारा 17 ए, जो सरकार को गैरकानूनी संगठन के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए स्थानों को अधिसूचित करने और कब्जा करने की शक्ति प्रदान करती है, उपखंड 2 (ए) और 2 (बी) को जोड़कर एक उपाय प्रदान किया गया था, जहां ऐसी शक्ति का उपयोग आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के तीस दिनों के भीतर, लघु कारण न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश को आवेदन के माध्यम से किया गया था, जैसा कि अधिसूचित स्थान प्रेसीडेंसी टाउन में या बाहर स्थित है, एक घोषणा के लिए कि उस स्थान का उपयोग किसी

गैरकानूनी संगठन के उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है। यदि ऐसी घोषणा की जाती है, तो सरकार उस स्थान के संबंध में अधिसूचना को रद्द कर देगी। धारा 17 बी एक अधिसूचित स्थान का कब्जा लेने वाले अधिकारी को उसमें पाई गई चल संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देती है, अगर उसकी राय में, ऐसी संपत्ति का उपयोग संकेतित प्रक्रिया का पालन करने के बाद "गैरकानूनी संगठन के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है"। इसी तरह धारा 17 ई सरकार को एक गैरकानूनी संगठन के धन को जब्त करने का अधिकार देती है "यदि वह ऐसी जांच के बाद संतुष्ट हो जाती है जो उसे उचित लगे कि इस तरह के धन का उपयोग किसी गैरकानूनी संगठन के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है या इसका उपयोग करने का इरादा है।" ऐसे मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। धारा 17 एफ द्वारा सिविल न्यायालयों की अधिकारिता, जैसा कि स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, धारा 17 ए से 17 ई के तहत की गई कार्यवाही के संबंध में वर्जित है।

संशोधन अधिनियम की धारा 6 द्वारा पहले से जारी और संशोधन से पहले रद्द नहीं की गई अधिसूचनाओं का प्रभाव इस तरह होना चाहिए जैसे कि वे धारा 15 (2) (बी) के तहत जारी की गई थीं, जैसा कि संशोधित किया गया था, और यह प्रदान किया गया है कि ऐसे मामलों में एक पूरक अधिसूचना भी जारी की जानी चाहिए जैसा कि धारा 16 (1) (ए) और (बी) में आवश्यक है जैसा कि संशोधित किया गया है और उसके बाद नई धारा 16-ए द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यह इस प्रावधान के तहत था

कि पुरानी धारा 16 के तहत 10 मार्च, 1950 को जारी अधिसूचना की वैधता पर संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए जब याचिका 21 अगस्त, 1950 को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आई।

यह देखा जाएगा कि जबकि पुरानी धारा 16 स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकार को संघों को गैरकानूनी घोषित करने की शक्ति प्रदान करती है, यदि उसकी राय में, उनके संबंध में कुछ निर्दिष्ट आधार मौजूद हैं, तो उन आधारों को अब धारा 15 (2) (बी) में संशोधित रूप में शामिल किया गया है, और सरकार की "राय" के संदर्भ को हटा दिया गया है। इससे हमारे सामने कुछ चर्चा हुई कि क्या धारा 15 (2) (बी) में निर्दिष्ट आधार, जैसा कि संशोधित किया गया है, उचित मुद्दे हैं या नहीं। यदि उन आधारों के तथ्यात्मक अस्तित्व को अदालत में जांच का विषय बनाया जा सकता है, तो संघ के अधिकार पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध अपवाद के लिए खुले नहीं होंगे, लेकिन तब सरकार ऐसा करेगी। स्पष्ट रूप से धारा 15 (2) (बी) का कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि, महान्यायवादी द्वारा उसकी ओर से यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया था कि एक परिभाषा खंड में इन आधारों को शामिल करने से, जिसने सरकार द्वारा गैरकानूनी होने की घोषणा की थी, उसकी राय में शब्दों को सम्मिलित किया गया था। अनावश्यक और वास्तव में अनुचित और यह कि उन शब्दों को छोड़ने से कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि जिन आधारों पर घोषणा आधारित होनी थी, वे पुरानी धारा 16 के तहत किसी भी अधिक उचित होने का इरादा रखते थे; विशेष रूप से सरकार या उसके अधिकारियों की "राय" या

"संतुष्टि" अभी भी धारा 17 ए (एल) के तहत किसी स्थान को अधिसूचित करने और धारा 17 बी (एल) के तहत उसमें पाए जाने वाले जंगलों को जब्त करने या धारा 17 ई (1) के तहत एक गैरकानूनी संघ के धन को जब्त करने में निर्धारक कारक है। सलाहकार बोर्ड के समक्ष ऐसे आधारों के अस्तित्व या अन्यथा के बारे में जांच के लिए प्रावधान और यदि बोर्ड ने पाया कि संघ को गैरकानूनी घोषित करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो अधिसूचना को रद्द करने के लिए भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचने का आग्रह किया गया था। विवाद बल के बिना नहीं है, और स्थिति प्रतिवादी के लिए नहीं लड़ी गई थी। तदनुसार, यह लिया जा सकता है कि धारा 15 (2) (बी) के तहत परीक्षण वैसा ही है जैसा कि पुरानी धारा 16 के तहत था, एक व्यक्तिपरक है, और आधारों का तथ्यात्मक अस्तित्व या अन्यथा एक उचित मुद्दा नहीं है।

"(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक वह सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाली कोई कानून लागू करता है, या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकता है।"

यह विवादित नहीं था कि विचाराधीन प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लगाए गए थे। लेकिन, क्या वे अर्थ या अनुच्छेद 19 (4) के भीतर "उचित" प्रतिबंध हैं?

इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, हम यह इंगित करना सही समझते हैं, जिसे कभी-कभी अनदेखा किया जाता है, कि हमारे संविधान में संविधान के अनुरूप कानून की न्यायिक समीक्षा के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं, अमेरिका के विपरीत जहां सर्वोच्च न्यायालय ने पांचवें और चौदहवें संशोधनों में व्यापक रूप से व्याख्या की गई "उचित प्रक्रिया" खंड की आड़ में विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की व्यापक शक्तियां ग्रहण की हैं। यदि, तब, इस देश में न्यायालयों को इस तरह के महत्वपूर्ण और कोई भी बहुत आसान कार्य का सामना करना पड़ता है, तो यह एक योद्धा की भावना से विधायी प्राधिकरण पर झुकने की किसी भी इच्छा से नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा उन पर स्पष्ट रूप से निर्धारित कर्तव्य के निर्वहन में है। यह विशेष रूप से "मौलिक अधिकारों" के संबंध में सच है, जिसके बारे में इस न्यायालय को एक प्रहरी की भूमिका सौंपी गई है। जबकि न्यायालय स्वाभाविक रूप से विधायी निर्णय को बहुत महत्व देता है, वह अंत में एक विवादित क़ानून की संवैधानिकता निर्धारित करने के अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता है। हमने इन स्पष्ट टिप्पणियों पर जोर दिया है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वर्गों में यह सुझाव दिया गया है कि नई व्यवस्था में अदालतें देश में विधानसभाओं के साथ टकराव की मांग कर रही हैं।

उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से अभिनिर्धारित किया कि धारा 15 (2) (बी) के तहत प्रतिबंध (1), अधिसूचना के प्रकाशन की अपर्याप्तता, (2) सरकार के लिए सलाहकार बोर्ड को कागजात भेजने या बाद वाले के लिए अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने में चूक, इस बीच दंड को लागू करने वाली सरकार के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, और (3) पीड़ित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व को ठीक करने के लिए अधिवक्ता के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार से इनकार करने के आधार पर उचित नहीं थे। इन आधारों के अलावा विद्वान न्यायाधीशों में से एक (न्यायमूर्ति

सत्यनारायण राव) ने कहा कि विवादित अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है जिसमें धारा 15 (2) (ए) और (बी) में उल्लिखित गैरकानूनी संघों के दो वर्गों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए कोई उचित आधार नहीं है। हालाँकि, अन्य विद्वान न्यायाधीश इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। न्यायमूर्ति विश्वनाथ शास्त्री ने आगे कहा कि विवादित अधिनियम में निहित संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान अमान्य थे क्योंकि उनका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से कोई उचित संबंध नहीं था। अन्य दो न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर कोई राय व्यक्त नहीं की। विद्वान न्यायाधीशों के इस निष्कर्ष से सहमत होते हुए कि धारा 15 (2) (बी) असंवैधानिक और अमान्य है, हमारी राय है कि निर्णय को व्यापक और अधिक मौलिक आधार पर रखा जा सकता है।

इस न्यायालय के पास डॉ. खरे के मामले में अनुच्छेद 19 के खंड (5) के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे को परिभाषित करने का अवसर था, जहां अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला वाक्यांश भी था। ऐसा होता है और निर्णय में भाग लेने वाले पांच में से चार न्यायाधीशों ने यह विचार व्यक्त किया (दूसरे न्यायाधीश ने प्रश्न को खुला छोड़ दिया) कि विवादित प्रतिबंधात्मक कानून के मूल और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं की जांच तर्कसंगतता के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए; अर्थात, न्यायालय को न केवल प्रतिबंधों की अवधि और सीमा जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए जिनके तहत उन्हें लागू करने को अधिकृत किया गया है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तर्कसंगतता का परीक्षण, जहां कभी भी निर्धारित किया गया हो, प्रत्येक व्यक्तिगत क़ानून पर लागू किया जाना चाहिए, और तर्कसंगतता का कोई अमूर्त मानक, या सामान्य पैटर्न, सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति, लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, बुराई की सीमा और तात्कालिकता को दूर करने की मांग, अधिरोपण का अनुपात, उस समय की प्रचलित

शर्तें, सभी को न्यायिक निर्णय में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह के मायावी कारकों का मूल्यांकन करने और किसी भी मामले की सभी परिस्थितियों में, जो उचित है, उसके बारे में अपनी अवधारणा बनाने में, यह अपरिहार्य है कि निर्णय में भाग लेने वाले न्यायाधीशों के सामाजिक दर्शन और मूल्यों का पैमाना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और ऐसे मामलों में विधायी निर्णय में उनके हस्तक्षेप की सीमा केवल उनकी जिम्मेदारी और आत्म-संयम की भावना और इस गंभीर प्रतिबिंब से निर्धारित की जा सकती है कि संविधान न केवल उनके सोचने के तरीके के लोगों के लिए है, बल्कि सभी के लिए है और जनता के अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधियों ने प्रतिबंधों को लागू करने को अधिकृत करने में उन्हें उचित माना है।

ऊपर बताए गए सभी विचारों को उचित महत्व देते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धारा 15 (2) (बी) को अनुच्छेद 19 (1) (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकार पर अधिकृत प्रतिबंधों की सीमाओं के भीतर आने के रूप में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। संघों या संघों के गठन के अधिकार के प्रयोग के लिए इतनी व्यापक और विविध गुंजाइश है, और इसकी कटौती धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में ऐसी संभावित प्रतिक्रियाओं से भरी हुई है, कि कार्यकारी सरकार को अपने तथ्यात्मक और कानूनी दोनों पहलुओं में इस तरह के अधिरोपण के आधारों को न्यायिक जांच में विधिवत परीक्षण की अनुमति दिए बिना, इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देना एक मजबूत तत्व है, जिसे हमारी राय में ध्यान में रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत मौलिक अधिकार के प्रयोग पर धारा 15 (2) (बी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का न्याय करना; क्योंकि, कोई सारांश नहीं है और जो एक सलाहकार बोर्ड द्वारा बड़े पैमाने पर एकतरफा समीक्षा होने के लिए बाध्य है, भले ही उसका निर्णय कार्यपालिका सरकार पर बाध्यकारी हो, न्यायिक जांच का विकल्प हो सकता है। सरकार या उसके अधिकारियों के व्यक्तिपरक संतुष्टि के सूत्र को, उन

सामग्रियों की समीक्षा करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड के साथ, जिन पर सरकार नागरिक को गारंटी दी गई बुनियादी स्वतंत्रता को ओवरराइड करना चाहती है, केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में और सबसे संकीर्ण सीमाओं के भीतर उचित माना जा सकता है, और मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों के सामान्य पैटर्न के रूप में न्यायिक अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सकता है निवारक निरोध के मामले में, निस्संदेह, इस न्यायालय ने गोपालन के मामले [1] [1950] एस.सी.आर. 88) में ऐसे साधनों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होने को बरकरार रखा, लेकिन इसका कारण यह था कि संविधान स्वयं निवारक निरोध के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों को मंजूरी देता है, जिसके बारे में अनुच्छेद 21 की भाषा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगतता का कोई सवाल नहीं उठ सकता था। जैसा कि कनिया सी.जे. ने बताया है। पृष्ठ 121 पर, रेक्स बनाम हैलिडे [2] [1917] एस.सी. 260, 269) में लॉर्ड फिनले को उद्धृत करते हुए; "अदालत उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए सबसे कम उपयुक्त न्यायाधिकरण थी जिन पर इस तरह की अग्रिम कार्रवाई काफी हद तक आधारित होनी चाहिए।"

महान्यायवादी ने डॉ. खरे के मामले [3] [1950] एस.सी.आर. 519 में निर्णय पर मजबूत भरोसा रखा, जहां किसी व्यक्ति को बाहर निकालने की आवश्यकता के बारे में सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि, एक सलाहकार बोर्ड को मामले के संदर्भ के साथ, जिसकी राय, हालांकि, कोई बाध्यकारी बल नहीं थी, को बहुमत द्वारा अनुच्छेद 19 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए "उचित" प्रक्रिया माना गया था। महान्यायवादी ने दावा किया कि उस निर्णय का तर्क वर्तमान मामले पर लागू होता है, क्योंकि विवादित अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट सरकार पर बाध्यकारी थी। हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि कई आवश्यक विवरणों में अंतर किया जा सकता है। एक बात के लिए. व्यक्तियों का निर्वासन, जैसे निवारक निरोध; काफी हद तक एहतियाती है और संदेह पर आधारित

है। वास्तव में, पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 4 ए (1), जो डॉ. खरे के मामले [(1)] [1950] एस.सी.आर. 519) में विचार का विषय थी, ने निवारक निरोध और निरोध दोनों को अधिकृत किया। उसी उद्देश्य के लिए और उसी आधार पर, अर्थात् "उसे सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिए यह आवश्यक है; आदि। इसके अलावा, दोनों में आपातकाल का एक तत्व शामिल है जिसमें सार्वजनिक शांति के लिए संभावित खतरे को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता होती है और अधिकार सरकार और उसके पास निहित होना चाहिए। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर उचित कार्रवाई करें। हालाँकि, ये विशेषताएं उन आधारों में अनुपस्थित हैं जिन पर सरकार को धारा 15 (2) (बी) के तहत संघों को गैरकानूनी घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। ये आधार; जो स्वयं लिए गए हैं, तथ्यात्मक हैं और अग्रिम या संदेह पर आधारित नहीं हैं। एक संगठन को गैरकानूनी घोषित करने की अनुमति है क्योंकि यह एक खतरे का गठन करता है या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करता है या अपने उद्देश्य के लिए इस तरह का हस्तक्षेप करता है। खंड (ख) के तहत अंतर्निहित तथ्यों की न्यायिक जांच को बंद करने की अपनी मात्र घोषणा द्वारा सरकार की मांग। दूसरा, पूर्वी पंजाब पब्लिक। सुरक्षा अधिनियम। यह एक अस्थायी अधिनियम था जो केवल एक वर्ष के लिए लागू होना था और इसके तहत किया गया कोई भी आदेश अधिनियम की समाप्ति पर समाप्त होने वाला था। जिसे इस तरह के क़ानून के तहत लगाए गए उचित प्रतिबंध के रूप में माना जा सकता है, उसे अनिवार्य रूप से विवादित अधिनियम के तहत उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाद वाला एक स्थायी उपाय है, और इसके तहत की गई कोई भी घोषणा अनिश्चित काल के लिए तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार इसे रद्द करने के लिए उचित नहीं समझती। तीसरा, जबकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवादित अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड की

प्रक्रिया पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत एक बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके तहत ऐसे निकाय की रिपोर्ट सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, विवादित अधिनियम संघ और उसके सदस्यों या पदाधिकारियों को धारा 15 (2) (बी) के तहत सरकार की अधिसूचना के पर्याप्त संचार के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में कहीं अधिक गंभीर दोष से ग्रस्त है। सरकार को अधिसूचना में पीड़ित व्यक्ति के लिए सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए एक उचित अवधि तय करनी होगी। लेकिन, जैसा कि पहले ही कहा गया है, किसी भी पदाधिकारी या संबंधित संघ के सदस्य पर कोई व्यक्तिगत सेवा या ऐसे संघ के कार्यालय में, यदि कोई हो, चिपकाकर कोई सेवा निर्धारित नहीं की गई है। न ही उस स्थान पर अधिसूचना की घोषणा का कोई अन्य तरीका प्रदान किया गया है जहां ऐसा संघ अपनी गतिविधियों को जारी रखता है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन, जिसका प्रचार मूल्य किसी भी तरह से बड़ा नहीं है, अवैध घोषित संघ के सदस्यों तक नहीं पहुंच सकता है, और यदि निर्धारित समय इस तरह की घोषणा के बारे में जानने से पहले समाप्त हो जाता है, तो प्रतिनिधित्व करने का उनका अधिकार, जो उनका मामला प्रस्तुत करने का एकमात्र अवसर है, खो जाएगा। फिर भी, सदस्यों के लिए परिणाम जो अधिसूचना में शामिल हैं, वे सबसे गंभीर हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी सदस्यता को धारा 17 के तहत अपराध बना दिया जाता है।

बार में इस बारे में कुछ चर्चा हुई कि क्या अधिसूचना की जानकारी का अभाव उस धारा के तहत अभियोजन में एक वैध बचाव होगा। लेकिन उस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संघ और उसके सदस्यों या पदाधिकारियों को ऐसी घोषणा के पर्याप्त संचार का प्रावधान किए बिना, दंडात्मक परिणामों के साथ किसी संघ को गैरकानूनी घोषित करने में शामिल अभियोजन का जोखिम, ऐसे साधनों से प्रतिबंध लगाने को अनुचित बनाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। इस संबंध में एक बहिष्करण आदेश एक अलग आधार पर खड़ा है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति पर व्यक्तिगत

या अन्य पर्याप्त सेवा के लिए प्रावधान किया गया है, जिसे इस प्रकार अपने मामले को आगे बढ़ाने के अवसर का आश्वासन दिया जाता है। इन सभी कारणों से डॉ. खरे के मामले (1) में निर्णय अलग है और वर्तमान मामले को नियंत्रित नहीं कर सकता है जैसा कि विद्वान महान्यायवादी द्वारा दावा किया गया है वास्तव में, जैसा कि हमने पहले देखा है, अनुच्छेद 19 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से एक पर लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता से संबंधित निर्णय का दूसरे अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता का निर्णय लेने के लिए एक उदाहरण के रूप में बहुत अधिक मूल्य नहीं हो सकता है, भले ही संवैधानिक मानदंड समान हो, अर्थात्, तर्कसंगतता, क्योंकि निष्कर्ष प्रत्येक मामले के अलग-अलग तथ्यों और परिस्थितियों के संचयी प्रभाव पर निर्भर होना चाहिए।

मामले को अपना सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक चिंतित विचार देने के बाद, हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के साथ सहमति में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि, उन विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, जिनके लिए संदर्भ दिया गया है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908 की धारा 15 (2) (बी), जैसा कि आपराधिक कानून संशोधन (मद्रास) अधिनियम, 1950 द्वारा संशोधित किया गया है, अनुच्छेद 19 के खंड (4) के तहत अधिकृत प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है और इसलिए, असंवैधानिक और शून्य है।

अपील विफल हो जाती है और तदनुसार लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

अपीलार्थी का अभिकर्ताः पी.ए. मेहता।

उत्तरदाता के लिए अभिकर्ताः एस. सुब्रमण्यन।

भारत संघ और त्रावणकोर-कोच्चि राज्य के लिए अभिकर्ताः पी.ए. मेहता।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक कैलाश पुनिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।